राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान की 162वीं बैठक के कार्यवृत्त

दिनांक **29.08.2024** को राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान की **162वीं** बैठक **श्रीमती बीना वहीद**, अध्यक्ष, एसएलबीसी राजस्थान की अध्यक्षता में आयोजित की गई। उक्त बैठक में श्री श्रीकांत नामदेव, निदेशक, वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, श्रीमती अनुप्रेरणा सिंह कुंतल, विशिष्ट शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, श्री पवन जैमन, संयुक्त शासन सचिव, वित्त मंत्रालय, राजस्थान सरकार, श्री नवीन नाम्बियार, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, जयपुर, डॉ. राजीव सिवाच, मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, जयपुर, श्री हर्षदकुमार टी. सोलंकी, संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान एवं महाप्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री विकास अग्रवाल, उप-महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, जयपुर, श्री अनुज अवस्थी, सहायक महाप्रबंधक, एसएलबीसी, राजस्थान सहित राज्य सरकार एवं भारत सरकार के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण, नाबार्ड, सिडबी, विभिन्न बैंकों, बीमा कम्पनियों व वित्तीय संस्थाओं के कार्यपालकों/ अधिकारियों द्वारा सहभागिता की गई। **(संलग्न सूची के अनुसार)**

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सर्वप्रथम मंच पर विराजमान गणमान्य उच्च अधिकारियों व राज्य सरकार के अधिकारी-गण, दोनों ग्रामीण बैंको के अध्यक्ष, सभी बैंकर्स, बीमा कंपनियों के अधिकारियों एवं समिति की बैठक में पधारे समस्त अतिथियों का राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान की 162वीं बैठक में स्वागत एवं अभिनंदन किया। उन्होने श्रीमती बीना वहीद, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति एवं कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा का उनकी प्रथम एसएलबीसी बैठक के लिए अभिनंदन एवं सम्मान किया।

उन्होने सदन को निम्नानुसार अवगत कराया-

- **Annual Credit Plan 2024-25:** वार्षिक साख योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए **रु 3,60,221.14 करोड़** का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसके सापेक्ष पहली तिमाही में **रु 1,38,600.85 करोड़ (38.48%)** की उपलब्धि की गयी है।
- सभी बैंक, विशेषकर जिन बैंकों ने पिछले वित्तीय वर्ष वार्षिक साख योजना के लक्ष्य उपलब्ध नहीं किए, से अनुरोध है कि इस वित्तीय वर्ष में वार्षिक साख योजना के Sector wise एवं कुल लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु उचित कार्ययोजना बनाते हुए कार्य करें।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

- **Expanding and Deepening of Digital Payment Ecosystem:** सभी सदय बैंकों ने सभी गैर-डिजिटल बचत व चालू खातों में अनुवर्ती कार्रवाई करने के बाद सभी पात्र बचत एवं चालू खातों में कम से कम एक डिजिटल उत्पाद प्रदान करने की प्रक्रिया पूरी कर ली है और बाद में खोले गए सभी खातों में भी कम से कम एक डिजिटल उत्पाद प्रदान करने के आश्वासन के साथ 100% डिजिटल डिस्ट्रिक्ट पुष्टिकरण के लिए प्रमाण पत्र प्रदान किया है जो हर्ष का विषय है।
- सभी बैंकों से अनुरोध है कि आगे भी, सभी नए बचत व चालू खातों में कम से कम एक डिजिटल उत्पाद प्रदान करवाना सुनिश्चित करें ताकि राजस्थान 100% डिजिटल राज्य बना रहे।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

तत्पश्चात उन्होंने राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान के अध्यक्ष एवं कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा को मुख्य उद्बोधन हेतु आमंत्रित किया।

अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान एवं कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा ने बैठक में मंचासीन सभी गणमान्य अथितियों एवं अन्य हितधारकों के अधिकारियों एवं राज्य और केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों का स्वागत किया।

उन्होने राज्य में हुए **Recent Developments** के संबंध में सदन को निम्नानुसार सूचित किया-

- **Brick & Mortar Branches**: DFS के निर्देशों के अनुसार, राजस्थान में Brick and Mortar Branch खोलने के लिए चिन्हित की गयी **108 Locations** में से जिन 4 केन्द्रों पर शाखा खोला जाना लंबित है, उनके आवंटी बैंकों से अनुरोध है कि वे बची हुई **Locations** पर जल्द से जल्द Branch खोलें।

(कार्यवाही: पंजाब नेशनल बैंक, आईडीएफ़सी फ़र्स्ट बैंक एवं भारतीय स्टेट बैंक)

- वित्तीय सेवाएँ विभाग, भारत सरकार द्वारा एक विशेष कार्यक्रम के तहत Key Performance Financial Inclusion Indicators यथा **PMJDY, PMJJBY** एवं **PMSBY** के तहत देश भर में न्यूनतम प्रदर्शन करने वाले 100 blocks को राज्य/राष्ट्रीय औसत के स्तर तक पहुंचाने हेतु identify किया गया है। राजस्थान में **ब्लॉक वैर, ज़िला भरतपुर, ब्लॉक झोथरी, ज़िला डुंगरपुर** एवं **ब्लॉक रानी स्टेशन, ज़िला पाली** को चयनित किया गया है। इन जिलों के अग्रणी ज़िला प्रबन्धकों से अनुरोध है कि त्वरित कार्यवाही करते हुए उक्त कार्यक्रम के तहत बैंकिंग सेवाओं से वंचित व्यक्तियों के PMJDY खाते खोल कर, उन्हे PMJJBY एवं PMSBY में Enrol करें।

(कार्यवाही: अग्रणी ज़िला प्रबन्धक भरतपुर, डूंगरपुर, पाली एवं समस्त सदस्य बैंक)

- राज्य सरकार द्वारा 31.07.2024 को MLUPY व MYUPY योजनाएँ बंद कर दी हैं। राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी बैंक इन योजनाओं के तहत लंबित आवेदनों का **31 अगस्त, 2024** तक निस्तारण करें, जिसके पश्चात शेष आवेदनों को अस्वीकृत माना जाएगा।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

- भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार भारत का **Financial Inclusion Index** मार्च 2023 में 60.1 के सापेक्ष मार्च 2024 में **64.2** रहा है।
- केंद्र सरकार ने **Raising and Accelerating MSME Performance (RAMP) programme** के तहत राजस्थान के लिए रु 114.80 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। यह फंड विकसित भारत-विकसित राजस्थान के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में MSMEs की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने में सहायता करेगा।

उन्होने राज्य में बैंकों के विभिन्न **key indicators जैसे Business Growth, Priority Sector Lending आदि** के संबंध में निम्नानुसार सूचित किया-

- वित्तीय वर्ष 2024-25 की जून तिमाही के अंत में राज्य के सभी बैंकों का Total Business **रु 13.63 लाख करोड़** पहुंच गया है। बैंकों ने Deposit में **11.28%** की Y-o-Y Growth की है और Advances में **18.61%** की Y-o-Y Growth की है।
- राज्य का CD Ratio जून, 2024 तक **95.22%** है और यह RBI Benchmark से काफी ऊपर है। **Advances to Priority Sector** ने **16.44%** की Y-o-Y Growth की है। Agriculture Advances में **12.20%** की Y-o-Y Growth हुई है एवं MSME Advances में **20.32%** की Y-o-Y Growth हुई है।
- Financial Year 2024-25 की जून तिमाही तक **Total Priority Sector** के ACP के लक्ष्यों के सापेक्ष Achievement **38.48%** है। ACP के तहत **MSME** में **45.35%**, **Agriculture** में **35.09%** और Other Priority Sector में **9.67%** उपलब्धि है।

Government Sponsored Schemes-

- सभी बैंकों, विशेषकर निजी बैंकों एवं स्माल फ़ाइनेंस बैंकों से अनुरोध है कि सरकारी योजनाओं, यथा, **PM SVANidhi, DAY NULM, Indira Mahila Shakti Udyam Protsahan Yojana (IMSUPY), SC-ST-POP, R-SETI Credit Linkage, SHG Credit Linkage, PMEGP एवं CGTMSE** के तहत अपने प्रदर्शन में सुधार करें।
- सभी बैंक **PMMY** के तहत लक्ष्यों को संबन्धित पोर्टल पर upload करें।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

उन्होने **सभी बैंक निम्न बिन्दुओ पर विशेष ध्यान देने का अनुरोध किया-**

1. **KCC Saturation Drive** में सभी पात्र किसानों को फसल एवं पशुपालन हेतु KCC Card दिया जाना।
2. बैंकिंग सेवाओं से वंचित सभी पात्र व्यक्तियों का PMJDY account खोलना और उन्हे सामाजिक सुरक्षा योजनाओं (**PMJJBY, PMSBY, APY**) से भी लाभान्वित करना।
3. PMJDY खातों में **Rupay card issuance** और activation तथा आधार seeding
4. कृषि क्षेत्र में **Investment Credit** में **40%** के राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुरूप प्रगति करना।
5. विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत सभी लम्बित आवेदन पत्रों में समय पर ऋण वितरित कराना।
6. '**Digital एवं Financial Literacy** का प्रचार-प्रसार।
7. **PM Vishwakarma योजना** के तहत सभी लम्बित आवेदन पत्रों में समय पर ऋण वितरित कराना।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

अंत में उन्होने **राजस्थान सरकार के पास समाधान हेतु लंबित बैंकों से संबन्धित मुद्दों** पर बैठक के दौरान राज्य सरकार से उचित समाधान प्राप्त होने की आशा व्यक्त की।

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने **क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक** को बैठक को संबोधित करने का निमंत्रण दिया।

क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक ने सदन को संबोधित करते हुए कहा कि-

- राजस्थान में लगभग 9 करोड़ CASA खातों में से सभी पात्र बचत एवं जमा खातों के digitization के साथ 100% डिजिटल राज्य बन गया है जो कि यह उपलब्धि करने वाला देश के पहले एक तिहाई राज्यों में से एक है। इस हेतु सभी बैंकों एवं इनमे कार्यरत field-level स्टाफ बधाई एवं अभिनंदन के पात्र हैं।
- PMJDY ने 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस योजना के माध्यम से बैंकिंग सेवाओं को देश के कोने कोने तक पहुंचाया गया है। राजस्थान में Basic Savings Accounts की औसतन जमा राशि गत 10 वर्षों में 5 गुना बढ़ कर लगभग रु 5000 के स्तर पर पहुँच गयी है जिसके सापेक्ष देश में Basic Savings Accounts की औसतन जमा राशि लगभग रु 4000 है।
- वित्त मंत्री, भारत सरकार एवं गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में बैंकों का ध्यान deposit mobilization की और इंगित किया है। देश में कुल जमा, GDP का लगभग 71% है जिसके सापेक्ष राजस्थान में कुल जमा GSDP का लगभाग 44% है। अतः राज्य में deposit mobilization की बहुत opportunity और scope है। सभी बैंक अधिक से अधिक deposit mobilization पर ज़ोर दें।
- राजस्थान का क्षेत्रफल देश के क्षेत्रफल का लगभग 10% है, किन्तु राज्य में कुल शाखाओं (8969) की प्रतिशत, देश की कुल शाखाओं (लगभग 1,53,000) के सापेक्ष इससे कम है जो संतोषजनक नहीं है। सभी बैंक अपने branch expansion plan में शाखाओं के यथोचित विस्तार पर विशेष ध्यान दें।
- देश के कुल ATM (लगभग 2,11,000) के सापेक्ष राजस्थान के क्षेत्रफल के अनुसार ATM की संख्या (लगभग 11,000) बहुत कम है। बैंक ATM सेवाओं का विस्तार करें जिससे जरूरतमन्द आवश्यकता पड़ने पर सुविधापूर्वक और समय पर बैंकिंग गतिविधिया कर सके।
- राजस्थान में बैंक मित्रों की संख्या सराहनीय है। बैंक मित्रों का उपयोग करके बैंक deposit mobilization को बढ़ावा दें एवं राज्य के सभी households को बैंकिंग के दायरे में लाएँ। अभी भी करीब 20% से ज्यादा households तक पहुँचने की आवश्यकता है।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

- राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान के डाटा representation में हर बैंक, अन्य बैंकों के सापेक्ष, सरकारी योजनाओं समेत सभी मापदंडों में अपना प्रदर्शन देख सकता है। इस उपलब्धि के लिए एसएलबीसी को बधाई।
- राज्य सरकार से अनुरोध है कि अपने field-level कार्मिको का उपयोग करके राज्य के ग्राम पंचायत स्तर पर हर ग्राम प्रधान से वहाँ कार्यरत बीसी का नाम/ आने-जाने का समय/ उपलब्ध कराई जा रही सेवाएँ, इत्यादि

जानकारी एकत्रित करें जिसके आधार पर यह विश्लेषण किया जा सके कि किन जगहों पर बैंक मित्रों की सेवाओं में सुधार करने की आवश्यकता है एवं मौजूदा बैंक मित्रों की निपुणता बढ़ाने हेतु कार्यवाही की जा सके। यह ग्रामीण क्षेत्रो में बैंकिंग सेवाओ की उपलब्धता एवं गुणवत्ता पर एक महत्वपूर्ण Feedback प्रक्रिया साबित होगी।

(कार्यवाही: आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार)

- राज्य सरकार से अनुरोध है कि बैंकर्स में विभिन्न सरकारी योजनाओ के संबंध में जागरूकता लाने हेतु कार्यक्रम किए जाए ताकि जमीनी स्तर पर भी विभिन्न योजनाओ की जानकारी पहुंचाई जा सके।

(कार्यवाही: आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार)

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने **निदेशक, वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, राजस्थान सरकार** को बैठक को संबोधित करने का निमंत्रण दिया।

निदेशक, वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, राजस्थान सरकार ने सदन को संबोधित करते हुए कहा कि-

- PMJDY के तहत बैंकों का प्रदर्शन प्रशंसनीय है जिसके लिए सभी बैंक बधाई के पात्र हैं।
- भारत सरकार की जिन योजनाओं की DFS, GoI के द्वारा निगरानी की जाती है, उन में एसएलबीसी राजस्थान का प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रहता है एवं लगभग हर parameter को उपलब्ध किया जाता है, इसके लिए एसएलबीसी एवं बैंक बधाई के पात्र हैं। इस सभी योजनाओं एवं parameters में प्रदर्शन अच्छा बनाए रखने एवं इसमे और भी सुधार करने के लिए सभी बैंक निरंतर प्रयास करें। उदाहरणतः बैंक, PMMY में ऋण वितरित करते समय दिशा-निर्देशानुसार सही ticket-size एवं PM-SVANidhi के आवेदनों का निर्धारित समय सीमा में निस्तारण करना सुनिश्चित करें।
- NPA खातों में ऋण वसूली बढ़ाने हेतु बैंक अधिक से अधिक लोक अदालतों का आयोजन करवाएँ।
- C-KYC पोर्टल पर हर व्यक्ति के लिए एक unique C-KYC number generate किया जाता है। बैंकों से अनुरोध है कि नया खाता खोलते समय उस नंबर के लिए search करें एवं उपलब्ध डाटा download करें। कोई डाटा उपलब्ध नहीं होने पर ही नया डाटा अपलोड करें ताकि उसका rejection ना हो।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

- राजस्थान सरकार से अनुरोध है कि सरफेसी के तहत दर्ज cases का निस्तारण नियमानुसार 30 दिनों एवं अधिक से अधिक 60 दिनों में करवाने हेतु संबन्धित ज़िला स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित करें।

(कार्यवाही: राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार)

मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड ने सदन को संबोधित करते हुए कहा कि-

- राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान की मुख्य बैठक का आयोजन लीड बैंक योजना के अनुसार निर्धारित समय सीमा मे करने हेतु एसएलबीसी टीम को बधाई।
- Economic Survey of India के अनुसार 2024-25 में भारत की वृद्धि दर 6.5-7.0% रहने का अनुमान है जबकि IMF के अनुसार वैश्विक वृद्धि दर 3.2% रहने का अनुमान है।
- कृषि ऋण के तहत राष्ट्रीय स्तर के प्रदर्शन के अनुरूप कार्य करने की आवश्यकता है।
- पशुपालन एवं मत्स्य पालन का कृषि में योगदान बढ़ते हुए लगभग 37% के स्तर पर पहुँच गया है।
- राष्ट्रीय बजट में कृषि हेतु रु 1.52 लाख करोड़ आवंटित किया गया है जिसके तहत focus areas इस प्रकार है- Agriculture Research Transformation, Climate Resistant Varieties, Mission of Pulses and Oilseeds, Vegetable Production और suppy chains की funding, Digital Public Infrastructure for Agriculture, Shrimp Production and export, इत्यादि।
- नाबार्ड द्वारा भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार की नीतियों के alignment में वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु PLP तैयार करने की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गयी है जिसे इस बार digital mode में तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है। यह projection 15 सितंबर 2024 तक अग्रणी ज़िला प्रबन्धकों के साथ साझा कर दी जाएगी और व्यापक परामर्श

के लिए इसे DCC बैठकों में भी प्रस्तुत किया जाएगा। इस बार PLP को District Credit Plan से संरेखित किया गया है।

- वित्तीय वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में 38% उपलब्धि रही है। सभी बैंकों से अनुरोध है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लक्ष्य उपलब्ध करना सुनिश्चित करें।
- वार्षिक साख योजना 2024-25 के तहत Other Priority Sector में प्रदर्शन असंतोषजनक है। सभी बैंक OPS के तहत अधिक से अधिक ऋण प्रदान करें। इस क्षेत्र में Renewable Energy के तहत कई ऋण प्रदान करने के कई अवसर हैं एवं केंद्रीय व राज्य सरकार का भी Renewable Energy पर ज़ोर है।
- कृषि क्षेत्र एवं OPS में Q-O-Q, क्रमशः 16% एवं 70% की नकारात्मक वृद्धि हुई है। इसे गंभीरता से लेने की एवं त्वरित सुधारात्मक कार्यवाही करने की आवश्यकता है।
- चालू वित्तीय वर्ष हेतु विभिन्न कृषि उत्पादों की unit cost जारी कर booklet के माध्यम से circulate कर दी गयी है जिसका उपयोग बैंक कृषि क्षेत्र में ऋण प्रदान करते समय कर सकते हैं। MSME क्षेत्र की unit cost की सूचना जल्द ही जारी की जाएगी।
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने AIF योजना की समय-अवधि एवं scope का विस्तार किया है। PM KUSUM Component A योजना समेत viable farming assets, integrated processing projects इत्यादि को इसमे सम्मिलित किया गया है। NABSanrakshan के माध्यम से AIF योजना में क्रेडिट गारंटी का भी प्रावधान है। सभी बैंकों से अनुरोध है कि AIF के तहत अधिक से अधिक ऋण प्रदान करें एवं निवेश/ सावधि कृषि ऋण में उपलब्धि प्रतिशत बढ़ाएँ।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

विशिष्ट शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार ने सदन को निम्नानुसार संबोधित किया-

- वर्तमान में बैंकिंग सेवाएँ client oriented हैं।
- सभी बैंकों से अनुरोध है कि गृह विभाग एवं राजस्थान पुलिस को investigation में पूर्ण सहयोग प्रदान करें।
- सभी बैंक अपने अधिकारियों/ कर्मचारियों को 161 CRPC के तहत बयान दर्ज करवाने में पूर्ण सहयोग करने का अनुरोध करे।
- सभी बैंक शाखाओं में 1930 साइबर क्राइम हेल्प-लाइन नंबर प्रदर्शित करावें।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, साइबर अपराध, राजस्थान ने बैंकों से निम्नानुसार अनुरोध किया-

- प्रदेश में digitization के साथ साथ साइबर अपराधों में भी गति आयी है।
- राष्ट्रीय साइबर क्राइम हेल्प लाइन नंबर 1930 पर रिपोर्ट करने पर संबन्धित बैंक खातों में त्वरित होल्ड लगाने की प्रक्रिया स्वचालित होनी चाहिए जिससे fraud राशि का स्थानांतरण अन्य खातों में किए जाने पर अंकुश लगाया जा सके।
- 1930 हेल्प लाइन पर प्रत्येक बैंक का 1 अधिकारी / कर्मचारी अपने बैंक से संबन्धित समन्वय हेतु नियुक्त किया जाना चाहिए। हरियाणा में ऐसा किया जा रहा है।
- राज्य स्तर पर सभी बैंकों के नोडल अधिकारी नियुक्त किए जावें जो शिकायतों में कार्यवाही हेतु 24 X 7 जवाबदेह हों।
- राज्य स्तर पर law enforcement agencies के नोडल अधिकारियों को सभी बैंकों में खातों की सूचना को ऑनलाइन access करने की सुविधा होनी चाहिए। जिससे law enforcement agency द्वारा आवश्यकता अनुसार संबन्धित बैंक खातों का स्टेटमेंट, खाता धारक का पता, मोबाइल नंबर व अन्य विवरण प्राप्त किया जा सके। संबन्धित बैंक अधिकारी द्वारा 65 B साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र एवं धारा 161 CRPC के बयान हेतु आनाकानी की जाती है। अनुसंधान अधिकारी द्वारा ATM की CCTV footage चाहने पर भी संबन्धित बैंकों द्वारा समय पर उपलब्ध कराई नहीं जाती।

- Google Play Store पर उपलब्ध ऑनलाइन ऋण ऐप्प के संबंध में नियंत्रण एवं निगरानी।
- बैंक खातों से linked संदिग्ध UPI Ids पर प्रभावी नियंत्रण एवं निगरानी।
- बैंक स्टेटमेंट में खाताधारकों द्वारा आय से अधिक लेन-देन पाये जाने पर नियंत्रण और निगरानी।
- बैंक द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले स्टेटमेंट में एकरूपता प्राण करना।
- इंटरनेट पर बैंकिंग संस्थाओं के फर्जी Toll-Free सहायता के नंबर उपलब्ध हैं जिनसे साइबर धोखाधड़ी हो रही है, उनपर प्रभावी नियंत्रण एवं निगरानी।
- परिवादी की freeze की गयी राशि को revert करने की प्रक्रिया का सरलीकरण हो एवं इसमे एकरूपता हो और law enforcement agency तथा bank system के तहत समन्वय हो।
- फर्जी डिजिटल खातों, mule खातों का भौतिक सत्यापन करवाने तथा ई-मित्र कियोस्क लाइसेंस धारकों जिनके द्वारा साइबर अपराध किया जा रहा हो, का भौतिक सत्यापन करना तथा उनपर निगरानी एवं नियंत्रण रखना।
- साइबर क्राइम हॉट-स्पॉट एरिया में बचत खातों की सीमा, ATM से राशि आहरण पर विशेष निगरानी।
- फर्जी फ़र्मों के खातों की पहचान एवं उनपर नियंत्रण एवं निगरानी करना।
- हॉट-स्पॉट इलाकों में ATM लगाने से संबन्धित नियम, guidelines में कठोरता की जानी चाहिए।
- एक ही शाखा में सैकड़ों की संख्या में mule खाते खुले होने के प्रकरण सामने आए हैं जिनमे नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

संयुक्त शासन सचिव, वित्त मंत्रालय, राजस्थान सरकार ने सदन को निम्नानुसार संबोधित किया-

- 1 सितंबर,2024 से अधिकतम केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के तहत निधि प्रवाह की प्रक्रिया को SNA Sparsh के माध्यम से किया जाना प्रारम्भ किया जाएगा। इस प्रक्रिया में सभी बैंकों से सहयोग अपेक्षित है।
- विभाग द्वारा सरकारी प्राप्तियों की अनुमति जल्द ही प्रदान की जाएगी।
- सभी बैंक राजस्थान में निवेश बढ़ाने हेतु विचार-विमर्श एवं कार्यवाही करें।
- सभी बैंक संपर्क पोर्टल पर प्राप्त होने वाली शिकायतों का निस्तारण कर, इनकी अद्यतित स्थिति से विभाग को अवगत कराएं।

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने मंचासीन गणमान्य सदस्यों एवं उपस्थित अन्य सभी सदस्यों का अभिवादन करते हुए अध्यक्ष महोदय की अनुमति पश्चात बैठक के विभिन्न कार्यवाही बिन्दुओं पर प्रस्तुतीकरण आरंभ किया:

Confirmation of Minutes of 161st SLBC Meeting (14.05.2024)

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सर्वप्रथम बताया कि दिनांक 14.05.2024 को आयोजित राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान की बैठक के कार्यवृत्त दिनांक 23.05.2024 को समस्त हितधारकों को प्रेषित किए गए हैं एवं इसकी पुष्टि करने के लिए सदन से अनुरोध किया, तत्पश्चात सदन में उपस्थित समस्त सदस्यों ने उक्त कार्यवृत की पुष्टि की।

Banking at a glance in Rajasthan

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि सभी मापदण्डों में प्रगति निम्नानुसार है-

Parameters	June, 2021	June, 2022	June,2023	March, 2024	June, 2024
No. of Branches (new Br in Yr./Qtr)	8,197 (16)	8,339 (23)	8,653 (42)	8,880 (348)	8969 (89)
*** 67.29% branches in Rural & Semi Urban.**					
					(₹. in Cr)
Deposits **(% Y-o-Y Growth)**	4,96,732 (9.67%)	5,53,997 (11.53%)	6,27,602 (13.29%)	6,90,918 (11.80%)	6,98,410 (11.28%)
Advances **(% Y-o-Y Growth)**	4,05,510 (11.92%)	4,76,789 (17.58%)	5,47,021 (17.60%)	6,53,698 (19.50%)	6,65,037 (18.61%)
CD Ratio	83.27%	87.55%	89.34%	94.61%	95.22%
PS Advances **(% Y-o-Y Growth)** **(% of total advances)**	2,57,304 (11.67%) (63.45%)	2,99,674 (16.47%) (62.85%)	3,41,204 (13.86%) (60.85%)	3,91,151 (17.58%) (59.84%)	3,97,307 (16.44%) (59.74%)
Agri. Advances **(% Y-o-Y Growth)** **(% of total advances)**	1,20,663 (10.29%) (29.76%)	1,38,444 (14.74%) (29.04%)	1,52,510 (10.16%) (27.20%)	1,69,893 (12.92%) (25.99%)	1,71,112 (12.20%) (25.73%)
MSME Advances **(% Y-o-Y Growth)** **(% of total advances)**	96,199 (16.14%) (23.72%)	1,23,561 (28.44%) (25.92%)	1,49,196 (20.75%) (26.61%)	1,73,620 (23.25%) (26.56%)	1,79,519 (20.32%) (26.99%)

Achievement against stipulated benchmark on June - 2024

सहायक महाप्रबंधक, **राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने सूचित किया कि-

- राज्य में सीडी अनुपात में **5.88%** की वृद्धि हुई है।
- प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र outstanding में **रु. 56,103 करोड़** की Y-O-Y बढ़ौतरी हुयी है।
- कृषि क्षेत्र outstanding में **रु. 18,602 करोड़** की Y-O-Y बढ़ौतरी हुयी है।
- माइक्रो खातों में **0.94%** की बढ़ौतरी हुयी है।
- एमएसएमई के तहत माइक्रो खातों की बकाया राशि में **रु. 19,086 करोड़** की Y-O-Y बढ़ौतरी हुई है। (नेट बढ़ौतरी)
- बैंकों को प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम, कृषि, कमजोर वर्ग अग्रिम और छोटे और सीमांत किसानों को ऋण देने पर विशेष ध्यान देना चाहिए क्योंकि पिछले 2-3 वर्षों से प्रतिशत के संदर्भ में गिरावट देखी जा रही है।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

Districts wise CD ratio in Rajasthan

No. of District	CD Ratio Range	Name of Districts
28	>100%	Anupgarh, Balotra, Baran, Barmer, Beawar, Bhilwara, Bikaner, Bundi, Chittorgarh, Churu, Didwana Kuchaman, Dudu, Sri Ganganagar, Hanumangarh, Jaipur Gramin, Jaisalmer, Jhalawar, Jodhpur Gramin, Kekri, Khairthal-Tijara, Kotputli-Behror, Nagaur, Neem Ka Thana, Phalodi, Pratapgarh, Sanchore, Sikar and Tonk
16	71-100%	Alwar, Banswara, Dausa, Deeg, Dholpur, Gangapur City, Jaipur Urban, Jalore, Jhunjhunu, Jodhpur Urban, Kota, Pali, Rajsamand, Salumbar, Sawai Madhopur and Shahpura
5	51-70%	Ajmer, Bharatpur, Dungarpur, Karauli and Udaipur
1	<50%	Sirohi

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने अग्रणी ज़िला प्रबन्धक, सिरोही एवं ज़िले में कार्यरत सभी बैंकों से अनुरोध किया कि सिरोही का सीडी अनुपात राज्य स्तर तक पहुंचाने हेतु mission-mode पर कार्य करें।

(कार्यवाही: अग्रणी ज़िला प्रबन्धक, सिरोही एवं समस्त सदस्य बैंक)

Districts having CD ratio lower than all India level (as on 30th June, 2024)

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सूचित किया कि राज्य के 13 जिलों यथा कोटा (76.72%), पाली (72.37%), भरतपुर (69.17%), झुंझुनू (75.79%), उदयपुर (65.63%), अजमेर (62.18%), राजसमंद (71.55%), करौली (68.32%), धौलपुर (70.79%), डूंगरपुर (59.70%), जोधपुर अर्बन (76.00%), जालोर (75.45%) एवं सिरोही (49.98%) का सीडी अनुपात, राष्ट्रीय औसत (79.49%) से कम है। सीडी अनुपात सुधारने हेतु इन जिलों में कार्यरत बैंक एवं अग्रणी ज़िला प्रबंधकों को मिशन मोड में कार्य करने का अनुरोध है।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक एवं अग्रणी ज़िला प्रबन्धक कोटा, पाली, भरतपुर, झुंझुनू, उदयपुर, अजमेर, राजसमंद, करौली, धौलपुर, डूंगरपुर, जोधपुर अर्बन, जालोर एवं सिरोही)

Comparative Development of Rajasthan from March' 24 to June' 24

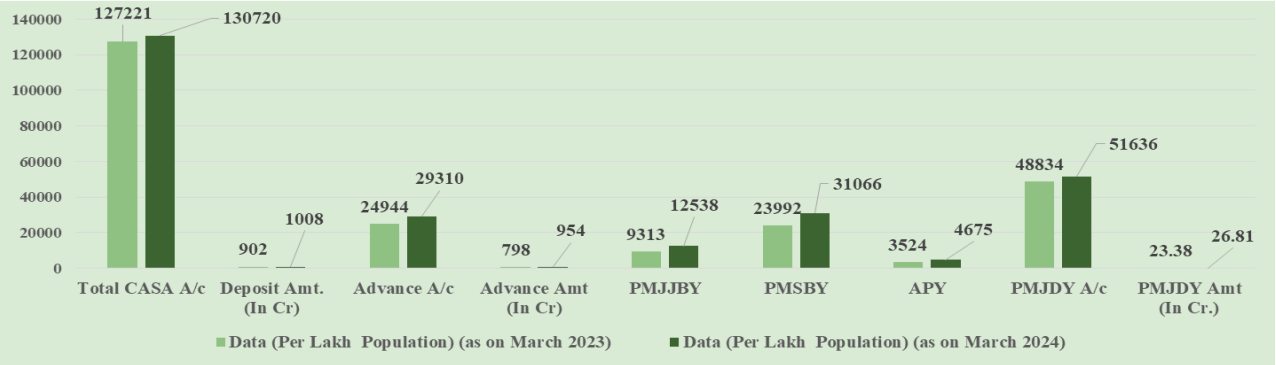

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सूचित किया कि मई के महीने में बीमाधारकों के बैंक खातों में पर्याप्त राशि नहीं होने के कारण कई PMJJBY एवं PMSBY पॉलिसी में नवीनीकरण नहीं हो पाया है जिसके कारण इनकी संख्या में कमी आयी है।

उप-महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक की टिप्पणी- सभी बैंक CASA खातों की संख्या में कमी आने के कारण की समीक्षा करें।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

Comparative Development of the Districts (Outstanding as on 30th June 2024)

1. **Branch penetration – No. of Branch per lakh population**
   सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने निम्नानुसार सूचित किया-
   - न्यूनतम प्रदर्शन वाले ज़िले- डीग (6), सांचोर (7), धौलपुर (7), बाड़मेर (7) एवं शाहपुरा (8)।
   - उच्चतम प्रदर्शन वाले ज़िले- जयपुर शहरी (29), जोधपुर शहरी (24), गंगानगर (21), अजमेर (18) एवं बीकानेर (16)
2. **Deposit penetration – No. of CASA A/c per lakh population**
   सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने निम्नानुसार सूचित किया-
   - न्यूनतम प्रदर्शन वाले ज़िले- पाली (66281), सीकर (61702), गंगानगर (61063), जयपुर शहरी (47889), जोधपुर शहरी (42205)।

- उच्चतम प्रदर्शन वाले ज़िले- जोधपुर ग्रामीण (152688), सालूम्बर (149779), अनूपगढ़ (135983), नीम का थाना (132288), दूदू (125336)।

3. **Credit penetration – No. of Advance A/c per lakh population**
   सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने निम्नानुसार सूचित किया-
   - न्यूनतम प्रदर्शन वाले ज़िले- करौली (13761), जोधपुर ग्रामीण (13475), डीग (13174), सालूम्बर (11445) एवं धौलपुर (10313)।
   - उच्चतम प्रदर्शन वाले ज़िले- जयपुर शहरी (88927), जोधपुर शहरी (55662), गंगानगर (42333), कोटपुटली-बहरोड़ (40038), हनुमानगढ़ (36152)।

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की टिप्पणी- जयपुर शहरी एवं जोधपुर शहरी ज़िले deposit penetration के तहत न्यूनतम प्रदर्शन वाले जिलों में प्रदर्शित हो रहे हैं, यह ब्लॉक स्तरीय डाटा की गलत mapping के कारण हो सकता है।

क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक ने एसएलबीसी से अनुरोध किया कि मार्च 2024 तिमाही के डाटा का संदर्भ लेकर जून 2024 तिमाही के डाटा की जांच करें।

उप-महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक ने SLBC से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया कि एसएलबीसी स्तर पर की गयी ब्लॉक mapping एवं बैंकों के internal system में की गयी ब्लॉक mapping एकरूप हैं।

(कार्यवाही: राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति)

Blocks having lowest CD ratio, per capita credit and per capita deposit (as on 30th June, 2024)

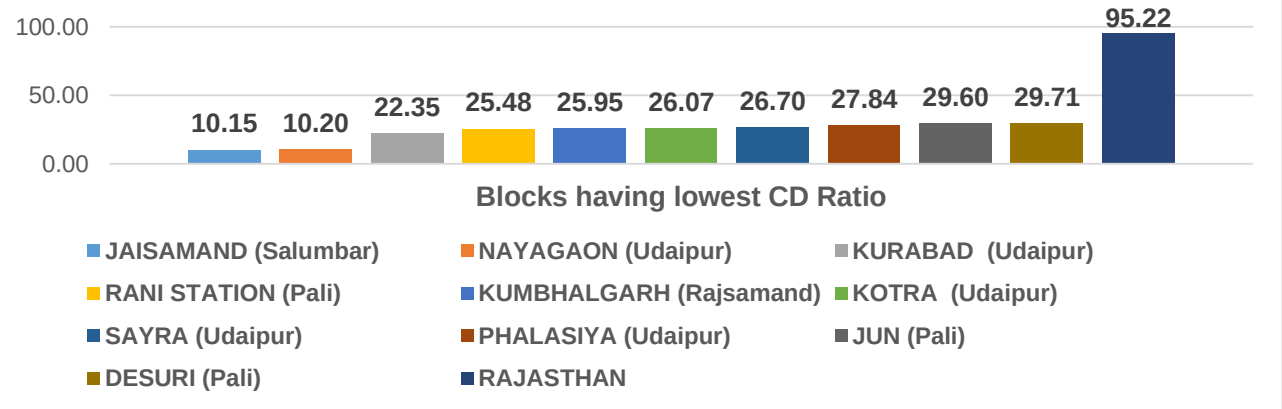

Annual Credit Plan F.Y. 2024-25

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सूचित किया कि वार्षिक साख योजना 2024-25 हेतु निर्धारित लक्ष्य **रु. 3,60,221 करोड़** के सापेक्ष 30 जून, 2024 तक क्षेत्र-वार उपलब्धि निम्नानुसार है-

- कृषि- 35.09%
- MSME- 45.35%
- अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र- 9.67%
- कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र- 38.48%

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सभी बैंकों से अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में प्रदर्शन सुधारने का अनुरोध किया।

क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक की टिप्पणी- राज्य में चालू खातों की संख्या, उद्यम पंजीकृत खातों की संख्या से अधिक है। बैंकों से अनुरोध है कि चालू खातों के उद्यमी खाताधारकों को उद्यम पंजीकरण करवाने के लिए प्रोत्साहित करें।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

Banks having performance below 30% under Annual Credit Plan (ACP) during F.Y. 24-25 (upto 30th June, 2024)

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने वार्षिक साख योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में जून 2024 तक **30% से कम** उपलब्धि वाले बैंक यथा पंजाब और सिंध बैंक (1.55%), राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक (25.72%), बैंक ऑफ महाराष्ट्र (8.88%), इंडियन ओवरसीज़ बैंक (21.65%), इंडियन बैंक (20.36%), एयू स्माल फ़ाइनेंस बैंक (19.79%), इंडसइंड बैंक (22.02%), यूको बैंक (23.33%), केनरा बैंक (23.35%) एवं पंजाब नेशनल बैंक (23.61%) से वित्तीय वर्ष 2024-25 में लक्ष्य के सापेक्ष शत-प्रतिशत उपलब्धि करने का अनुरोध किया।

(कार्यवाही : बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब और सिंध बैंक, राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, इंडियन बैंक, एयू स्माल फ़ाइनेंस बैंक, इंडसइंड बैंक, यूको बैंक, केनरा बैंक एवं पंजाब नेशनल बैंक)

प्रतिनिधि, पंजाब एंड सिंध बैंक ने आगामी तिमाही में प्रदर्शन सुधारने का आश्वासन दिया।

प्रतिनिधि, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने सूचित किया कि बैंक के द्वारा एक नयी योजना के तहत MSME के प्रचार के लिए 3 clusters का निर्माण किया गया है एवं सितंबर तिमाही के अंत तक प्रदर्शन में सुधार करने का आश्वासन दिया। कृषि ऋण बढ़ाने हेतु भी बैंक प्रयासरत हैं।

क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक की टिप्पणी-

- LBS के मास्टर परिपत्र के अनुसार एसएलबीसी की मुख्य बैठक में बैंकों द्वारा उच्च स्तरीय सहभागिता होनी चाहिए।
- वित्तीए समावेशन के विभिन्न मापदंड, सरकारी योजनाओ में pendency इत्यादि के आधार पर बैंकों की रेंकिंग की जायें एवं जिन बैंकों में आगामी तिमाही में उचित सुधार नहीं होता है तो उसे अगले स्तर पर escalate किया जाये।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक, SLBC)

Annual Credit Plan 2024-25:

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सूचित किया कि-

- वित्तीय वर्ष 2023-24 के एसीपी लक्ष्य **रु 2,79,855 करोड़** रहे जिसके सापेक्ष ACP उपलब्धि **रु 3,08,071 करोड़** रही है।
- वित्तीय वर्ष 2024-25 में नाबार्ड द्वारा **रु 3,62,152 करोड़** का पीएलपी प्रॉजेक्शन प्रेषित किया गया है। इसके आधार पर वित्तीय साख योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु डीसीसी द्वारा **रु 3,60,221 करोड़** का लक्ष्य अनुमोदित किया गया है जो पिछले वित्तीय वर्ष की उपलब्धि से **16.93%** अधिक है।
- सभी बैंकों से अनुरोध है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के वार्षिक साख योजना के क्षेत्रवार, गतिविधि-वार प्रदर्शन का विश्लेषण करें क्योंकि कुछ जिलों में OPS के तहत प्रदर्शन निराशाजनक है।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

- अग्रणी ज़िला प्रबन्धक हर वर्ष जून के दौरान एक प्री-पीएलपी बैठक बुलाएं और सभी हितधारक क्रेडिट क्षमता (सेक्टर/गतिविधि-वार) के बारे में अपने विचार प्रकट करें और पिछले एक वर्ष में जिले में प्रमुख वित्तीय और सामाजिक-आर्थिक विकास पर विचार-विमर्श करेंगे। पीएलपी में सम्मिलित करने के लिए प्राथमिकताएं निर्धारित की

जाएं। नाबार्ड के डीडीएम अगले वर्ष के लिए पीएलपी तैयार करने के लिए सूचना की प्रमुख आवश्यकताओं को रेखांकित करते हुए प्री-पीएलपी बैठक में एक प्रस्तुतिकारण दें।

(कार्यवाही: समस्त अग्रणी ज़िला प्रबन्धक एवं नाबार्ड)

Agency wise snapshot of Investment Credit under Agriculture (as on 30.06.2024)

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सूचित किया कि दिनांक 30.06.2024 तक वाणिज्यिक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक एवं स्माल फ़ाइनेंस बैंकों का कुल कृषि अग्रिम के सापेक्ष निवेश ऋण क्रमशः **35.67%, 7.78%, 7.86% एवं 99.74%** हैं।

दिनांक 30.06.2024 तक राजस्थान राज्य के कुल कृषि ऋण में निवेश ऋण की प्रतिशत (30.58%) से कम प्रतिशत वाले बैंक निम्नानुसार हैं- आरएमजीबी (2.34%), सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (5.86%), यूको बैंक (10.12%), राजस्थान राज्य सहकारी बैंक (4.24%), भारतीय स्टेट बैंक (10.86%), केनरा बैंक (12.55%), बीआरकेजीबी (10.22%), पंजाब और सिंध बैंक (12.15%), इंडियन बैंक (11.78%), बैंक ऑफ बड़ौदा (23.97%), पंजाब नेशनल बैंक (14.93%), आईडीबीआई (8.67%), जम्मू एंड कश्मीर (10.25%), फेडरल बैंक (12.65%), कैपिटल स्माल फ़ाइनेंस बैंक (20.73%)।

उक्त बैंकों से अनुरोध है कि कुल निवेश ऋण कुल कृषि ऋण के 40% तक बढ़ाने हेतु कार्ययोजना बनाकर अग्रिम कार्यवाही करें।

(कार्यवाही: आरएमजीबी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, राजस्थान राज्य सहकारी बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, केनरा बैंक, बीआरकेजीबी, पंजाब और सिंध बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक आईडीबीआई, जम्मू एंड कश्मीर, फेडरल बैंक, कैपिटल स्माल फ़ाइनेंस बैंक)

प्रतिनिधि, आरएमजीबी ने सूचित किया कि पिछले वित्तीय वर्ष के सापेक्ष बैंक का कृषि निवेश ऋण 5 गुना बढ़ा है।

Setting up of Brick-and-Mortar Branches Status as on 27.08.2024

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि राजस्थान में ब्रिक और मोर्टार शाखाएं खोलने के लिए चिन्हित **108 (95+13)** स्थानों में से **33 (30+3)** केन्द्रों पर पहले से शाखा खुली हुई हैं एवं शाखाओं को जन धन दर्शक ऐप्प पर अद्यतित कर दिया गया है। दिनांक 30.04.2024 तक **71 (63+9)** केन्द्रों पर शाखा खोली जा चुकी हैं एवं **04** केन्द्रों पर ब्रिक और मोर्टर शाखा खोलना लंबित है जिसकी स्थिति निम्नानुसार है-

BANK WISE STATUS OF ALLOCATION OF IDENTIFIED LOCATIONS FOR BRICK & MORTAR BRANCHES						
Sr. no.	**District**	**Sub District**	**Village Code**	**Village Name**	**Population**	**Allotment to Banks (05.09.2022 & 18.04.2023)**
1	Barmer	Chohtan	88879	Beejasar	4797	Punjab National Bank
2	Jodhpur (Rural)	Osian	084511	Ompura	4173	IDFC FIRST Bank
3	Jodhpur (Rural)	Tinwari	084709	Beenj Wariya	4306	IDFC FIRST Bank
4	Jaisalmer	Pokaran	86330	Madwa	3423	State Bank of India

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सूचित किया कि माडवा में IPPB केंद्र खुल गया है जिसके कारण यह केंद्र अब unbanked नहीं है। अतः इस केंद्र को unbanked गांवों की सूची से हटाने के लिए डीएफ़एस, भारत सरकार के साथ अनुवर्ती कार्यवाही चल रही है।

प्रतिनिधि, **आईडीएफ़सी बैंक** ने बींजवारिया में 31.08.2024 एवं ओमपुरा में आगामी महीने तक शाखा खोलने का आश्वासन दिया।

प्रतिनिधि, **पंजाब नेशनल बैंक** ने सूचित किया कि राज्य सरकार के विभाग द्वारा स्थानीय प्रशासन को बीजासर में शाखा खोलने हेतु चिन्हित परिसर में मरम्मत इत्यादि का आवश्यक कार्य करवाने हेतु निर्देश दिया गया है। उन्होने 2-3 दिनों में शाखा खोलने का आश्वासन दिया।

संयुक्त शासन सचिव, **आयोजना विभाग**, **राजस्थान सरकार** की टिप्पणी- उक्त बैंकों से अनुरोध है कि दिनांक 13.09.2024 को होने वाली NZC बैठक से पूर्व शेष आवंटित केन्द्रों पर शाखाएँ खोलें।

(कार्यवाही: पंजाब नेशनल बैंक एवं आईडीएफ़सी फ़र्स्ट बैंक)

Uncovered villages within 5KM radius

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि वित्तीय सेवाएँ विभाग, भारत सरकार ने ई-मेल दिनांक 01.07.2024 के माध्यम से 5 किमी के दायरे तक बैंकिंग आउटलेट से वंचित 16 ग्रामों की सूची दी है, जिनको राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति द्वारा ई-मेल दिनांक 04.07.2024 के माध्यम से सदस्य बैंकों को आवंटित कर दिया गया है। इन केन्द्रों पर बैंकिंग आउटलेट खोले जाने की 27.08.2024 तक की स्थिति निम्नानुसार है-

Status of Uncovered Villages within 5 KM radius as on 27.08.2024				
Sr. No.	**Name of Bank**	**Total No. of Uncovered Villages**	**Total Villages Covered**	**Remaining Uncovered Villages**
1	AU BANK (SFB)	1	1	0
2	AXIS BANK	2	0	2
3	BANK OF BARODA	5	5	0
4	INDIAN BANK	2	0	2
5	PUNJAB NATIONAL BANK	2	2	0
6	RMGB	3	3	0
7	STATE BANK OF INDIA	1	1	0
	Grand Total	**16**	**12**	**4**

प्रतिनिधि, एक्सिस बैंक ने आवंटित केन्द्रों में जल्द-से-जल्द बैंक मित्र नियुक्त करने का आश्वासन दिया।

प्रतिनिधि, इंडियन बैंक ने सूचित किया कि रूपनगर में बैंक मित्र चिन्हित कर लिया गया है एवं KO Code बनाने की प्रक्रिया जारी है। अमरपुरा में सितंबर 2024 तक बैंक मित्र नियुक्त करने का आश्वासन दिया।

उप-महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक ने उक्त बैंकों से अनुरोध किया कि यदि बैंक मित्र बनाने हेतु उपयुक्त व्यक्ति नहीं मिलने पर स्वयं सहायता समूहों की IIBF certified महिलाओं को बैंक सखी के रूप में नियुक्त करें।

प्रतिनिधि, राजीविका, राजस्थान सरकार ने उक्त बैंकों से राजीविका विभाग से संपर्क करने का अनुरोध किया एवं ऐसा किए जाने पर उपयुक्त बैंक सखी से संपर्क करवाने का आश्वासन दिया।

(कार्यवाही: एक्सिस बैंक एवं इंडियन बैंक)

State/ UT wise Inactive Fixed Point BC data

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने सदन को विभिन्न बैंकों में BC inactivity प्रतिशत से निम्नानुसार अवगत कराया-

बैंक ऑफ बड़ौदा- 10.49%, एचडीएफ़सी बैंक- 12.32%, आईडीएफ़सी बैंक- 17.33%, यूको बैंक- 21.71%, बैंक ऑफ इंडिया- 31.26%, पेटीएम पेमेंट्स बैंक- 35.39%, कैपिटल स्माल फ़ाइनेंस बैंक- 50.00%, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक- 54.76%, फैनो पेमेंट्स बैंक- 72.39%, केनरा बैंक- 78.83%। उक्त बैंकों से असक्रिय बैंक मित्रों को सक्रिय/ प्रतिस्थापित करने का अनुरोध है।

(कार्यवाही: बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफ़सी बैंक, आईडीएफ़सी बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, पेटीएम पेमेंट्स बैंक, कैपिटल स्माल फ़ाइनेंस बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, फैनो पेमेंट्स बैंक, केनरा बैंक)

प्रतिनिधि, केनरा बैंक ने सूचित किया कि इतनी अधिक संख्या में inactive बैंक मित्रों का होना, बैंक के लिए भी चिंता का विषय है। बैंक के द्वारा कई बार संबन्धित BC agency के साथ बैठकें की गईं हैं किन्तु inactive बैंक मित्रों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। बैंक के अंचल कार्यालय, जयपुर ने बैंक के प्रधान कार्यालय से BC Agency के साथ बैंक के contract की पुनः समीक्षा करने एवं नयी BC agency को contract देने का अनुरोध किया है।

Saturation Drive for Jan Suraksha Schemes

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि जन सुरक्षा योजनाओं के संतृप्ति अभियान के तहत प्रगति इस प्रकार है:

Special Drive for Jan Suraksha Scheme						
As on date	PMJJBY		PMSBY		APY	
	Target	Enrolled	Target	Enrolled	Target	Enrolled
01.05.2024	69,15,500	36,44,562 (53%)	96,73,911	78,07,264 (81%)	56,33,175	11,57,106 (21%)
07.08.2024	69,15,500	40,04,850 (58%)	96,73,911	81,92,249 (85%)	56,33,175	**12,96,765 (23%)**
Progress		**360,288**		**384,985**		**139,659**

सभी बैंकों से अनुरोध है कि वह वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 20.04.2022 के माध्यम से सूचित किए गए, संतृप्ति अभियान के संशोधित लक्ष्यों के अनुरूप, जन सुरक्षा योजनाओं यथा PMJJBY, PMSBY एवं APY के तहत **सितंबर 2024** तक **100%** लक्ष्य उपलब्धि करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

Atal Pension Yojna FY 2024-25:

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सूचित किया कि राज्य में कुल **6,34,080** नामांकन के लक्ष्य के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2024-25 में दिनांक 15.08.2024 तक 2,22,033 **(35%)** नामांकन किए गए हैं।

अटल पेंशन योजनान्तर्गत **एजेंसी-वार** उपलब्धि निम्नानुसार है-
सार्वजनिक बैंक- 38%
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक- 46%
स्माल फ़ाइनेंस बैंक- 25%
एचडीएफ़सी, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, आईडीबीआई बैंक- 5%
अन्य निजी बैंक- 32%
सहकारी बैंक- 0.50%

स्माल फ़ाइनेंस बैंकों एवं निजी बैंकों से, विशेषकर **एचडीएफ़सी, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक एवं आईडीबीआई बैंक** से अनुरोध है कि अटल पेंशन योजना में सक्रिय भागीदारी करते हुए अपने प्रदर्शन में सुधार करें।

Deepening of Digital Payments Ecosystem:

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सदन को सूचित किया कि सभी बैंकों के समुचित प्रयासों के कारण राजस्थान 100% डिजिटल राज्य बन गया है। इस के लिए सभी बैंक बधाई के पात्र हैं।

उन्होने सूचित किया कि दिनांक 30.06.2024 तक राज्य में **7.28 करोड़ बचत खातों** एवं **19.13 लाख चालू खातों** को digitize किया गया है।

Support required from State Governement

सहायक महाप्रबन्धक, **राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने राज्य सरकार के संबन्धित विभाग को आर-सेटी भवन निर्माण से संबन्धित विभिन्न मुद्दों का निस्तारण करने एवं की गयी कार्यवाही से सदन को अवगत कराने का अनुरोध किया।

(कार्यवाही: ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग एवं राजस्व विभाग, **राजस्थान सरकार)**

संयुक्त शासन सचिव, **आयोजना विभाग**, **राजस्थान सरकार** ने ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार से प्रश्न किया कि एसएलबीसी की स्टियरिंग समिति में हुए निर्णय के अनुसार**,** उक्त प्रकरण के संबंध में अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव के स्तर पर बैठक आयोजित क्यों नहीं की गयी है? उन्होने विभाग से अनुरोध किया कि इस प्रकरण पर चर्चा करने हेतु मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में बैठक करावें।

(कार्यवाही: ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, **राजस्थान)**

प्रतिनिधि, **राजीविका**, **राजस्थान सरकार** ने सूचित किया कि उक्त संबंध में आर-सेटी निदेशक की शासन सचिव**,** RGPRS, राजस्थान सरकार के साथ बैठक हो चुकी है। उन्होने ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार को बैठक में हुई चर्चा के संबंध में अवगत कराने आर-सेटी भवन निर्माण से संबन्धित विभिन्न मुद्दों की वर्तमान स्थिति की सूचना हितग्राहकों को प्रदान करने का अनुरोध करने का आश्वासन दिया।

राज्य निदेशक, **आर-सेटी**, **भारत सरकार** ने सदन को सूचित किया कि-

- आर-सेटी भवन निर्माण से संबन्धित विभिन्न मुद्दों में अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई है।
- किसी भी नए ज़िले में आर-सेटी नहीं खुली है। यूको बैंक के अतिरिक्त किसी भी बैंक द्वारा आर-सेटी के प्रस्ताव MoRD, भारत सरकार को आधिकारिक अनुमोदन के लिए नहीं भेजे गए हैं।

Amendment in PDR Act, 1952

सहायक महाप्रबन्धक, **राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने सूचित किया कि-

- राज्य सरकार के संबन्धित विभाग से**,** PDR Act, 1952 में संशोधन कर विभिन्न सरकारी ऋण योजनाओं में बैंकों की बकाया राशि की वसूली को शामिल करने हेतु कार्यवाही करने का अनुरोध किया।

(कार्यवाही: राजस्व विभाग, **राजस्थान सरकार)**

RACO RODA & SARFAESI Act

- प्रकरण बकाया दिनांक 30.06.2024 तक
  - RACO RODA - 1,47,619 Cases Amt. ₹. 3,762 Cr
  - SARFAESI Act - 3,015 Cases Amt. ₹. 312 Cr.

सहायक महाप्रबन्धक, **राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने राज्य सरकार के संबन्धित विभाग से उक्त मुद्दे पर कार्यवाही करने का अनुरोध किया।

(कार्यवाही: राजस्व विभाग, **राजस्थान सरकार)**

संयुक्त शासन सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार ने सूचित किया कि सभी ज़िला कलक्टरों को राको-रोडा एवं सरफेसी के तहत नए cases स्वीकृत करने एवं लंबित cases का निस्तारण करने हेतु DO पत्र के माध्यम से निर्देशित कर दिया गया है। साथ ही अनुरोध किया है कि अप्रत्याशित परिस्थितियों का सामना कर रहे ऋणियों के संबंध में मानवीय दृष्टिकोण से कार्यवाही करें तथा अन्य प्रकरणों में अधिनियम के अनुसार कार्यवाही करें।

यदि बैंक किसी ज़िले में विशेष रूप से समस्या का सामना कर रहे हैं, तो आयोजना विभाग के संज्ञान में लाएँ।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

Waiver in Glow Sign Board Charges (Pending since June 2017)

सहायक महाप्रबन्धक, **राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने सूचित किया कि स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार ने ग्लो साइन बोर्ड (बैंक शाखा की जानकारी) प्रदर्शित करने पर लगने वाले शुल्क को माफ नहीं करने का निर्णय लिया है। एसएलबीसी एवं बैंकों से अनुरोध है कि शुल्फ माफी के संबंध में मुख्य सचिव महोदय से समय लेकर मिलें एवं पुनः अनुरोध करें।

(**कार्यवाही: राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति एवं समस्त सदस्य बैंक)**

Property cards issued under Svamitva Scheme

सहायक महाप्रबंधक, **राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने सूचित किया कि-

- SVAMITVA योजना बसे हुए ग्रामीण इलाकों में घर रखने वाले गांव के घरेलू मालिकों को 'अधिकारों का रिकॉर्ड' प्रदान करेगी, बदले में, उन्हें बैंकों से ऋण और अन्य वित्तीय लाभ लेने के लिए वित्तीय संपत्ति के रूप में अपनी संपत्ति का उपयोग करने में सक्षम बनाएगी। जिसके तहत ग्रामीणों को वित्तीय साधन के रूप में प्रोपर्टी कार्ड जारी किया जावेगा जो संपार्श्विक के रूप में काम करेगा।
- राजस्थान राज्य में आवासीय उद्देश्य के लिए आबादी भूमि के पट्टे ग्राम पंचायत द्वारा जारी किए जाते हैं, न कि स्वामित्व योजना में निर्दिष्ट प्रॉपर्टी कार्ड।
- पट्टे पर "डिफॉल्ट के मामले में संपत्ति की बिक्री नहीं करने" की शर्त है जो बैंकों को SARFAESI अधिनियम 2002 के तहत सुरक्षा लागू करने के लिए प्रतिबंधित करती है।
- उक्त पट्टे के आधार पर निर्माण कार्य के अतिरिक्त किसी प्रायोजन के लिए ऋण देने का प्रावधान नहीं है।
- संबन्धित विभाग से अनुरोध है कि वह पट्टों के आधार पर दिये जा रहे ऋण को स्वामित्व योजना के तहत की गयी प्रगति में सम्मिलित करने हेतु MoPR, भारत सरकार से अनुरोध करें अन्यथा राजस्थान की स्वामित्व योजना के तहत प्रगति शून्य परिलक्षित होगी।

(कार्यवाही: ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार)

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने संबन्धित विभाग से अनुरोध किया कि पट्टे पर ऋण दिये जाने में उक्त बाधाओं का संज्ञान लेवें एवं भारत सरकार के निर्देशानुसार राज्य में स्वामित्व योजना का क्रियान्वयन करें अथवा पट्टे के नियम एवं शर्तों में संशोधन कर उसे स्वामित्व योजना के तहत जारी किए जाने वाले स्वामित्व कार्ड से समरूप करें। यदि पट्टे के आधार पर अन्य गतिविधियों के लिए ऋण प्रदान करने का प्रावधान हो तो OPS के तहत प्रदर्शन में सुधार होगा।

(कार्यवाही: ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार)

क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि पट्टे एवं स्वामित्व कार्ड के संबंध में राज्य सरकार एवं केंद्रीय सरकार की नीतियाँ भिन्न होने के कारण, राज्य में formal credit dissemination में समस्या आ रही है।

Reduction in Frequency of DLRC meetings

सहायक महाप्रबंधक, **राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने सूचित किया कि-

- क्योंकि जन प्रतिनिधि डीएलआरसी फोरम के सबसे महत्वपूर्ण घटक हैं, इसलिए अग्रणी ज़िला प्रबन्धकों को सांसदों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए डीएलआरसी बैठकों की तारीखें तय करनी चाहिए और एजेंडा पत्रों को पहले ही सांसदों को वितरित करना चाहिए।

(कार्यवाही: समस्त अग्रणी ज़िला प्रबन्धक)

- हालाँकि, यह देखा गया है कि अधिकांश जन प्रतिनिधियों को समय की कमी होने के कारण डीएलआरसी बैठकों में जन प्रतिनिधियों की भागीदारी बहुत कम है और अधिकांश समय डीसीसी बैठकों के प्रतिभागी ही डीएलआरसी बैठक में भाग ले रहे हैं।
- उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह प्रस्तावित किया जाता है कि डीएलआरसी बैठक की आवृत्ति को त्रैमासिक से घटाकर अर्धवार्षिक/वार्षिक आधार पर किया जाए और जन प्रतिनिधियों, अर्थात संबंधित स्थानीय सांसदों/विधायकों/जिला परिषद प्रमुखों द्वारा दी गई दिनांक और समय के अनुसार डीएलआरसी का आयोजन किया जाए।

संयुक्त शासन सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार ने सूचित किया कि उनके द्वारा सभी ज़िला कलक्टरों को डीएलआरसी बैठकों में जन प्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित करवाने हेतु पत्र दिनांक 14.05.2024 एवं 24.06.2024 के माध्यम से अनुरोध किया गया है। उन्होने राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति से जुलाई एवं सितंबर, 2024 तिमाही की डीएलआरसी बैठकों में जन प्रतिनिधियों की भागीदारी का डाटा उपब्ध कराने हेतु अनुरोध किया जिसका विश्लेषण करने के बाद संबन्धित ज़िला कलक्टर से जन प्रतिनिधी की अनुपस्थिति पर चर्चा करने का उन्होने आश्वासन दिया।

(कार्यवाही: राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति एवं आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार)

क्षेत्रीय प्रबन्धक, भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी अग्रणी ज़िला प्रबन्धकों से अनुरोध किया कि Financial Inclusion and Development Department, भारतीय रिजर्व बैंक को जुलाई एवं सितंबर, 2024 तिमाही की डीएलआरसी बैठकों में जन प्रतिनिधियों की भागीदारी का डाटा प्रदान करें ताकि संबन्धित ज़िला कलक्टर के साथ उक्त मुद्दे पर चर्चा की जा सके।

(कार्यवाही: समस्त अग्रणी ज़िला प्रबन्धक)

उप-महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक की टिप्पणी- अग्रणी ज़िला प्रबन्धकों द्वारा जन प्रतिनिधियों को डीएलआरसी की बैठक में सहभागिता करने हेतु आमंत्रित किया जाता है एवं इस हेतु अनुवर्ती कार्यवाही भी की जाती है।

प्रतिनिधि, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सूचित किया कि 24 जिलों की मार्च 2024 तिमाही की डीएलआरसी बैठकों में जन-प्रतिनिधियों द्वारा सहभागिता नहीं की गयी।

PM Street Vendor's Atmanirbhar Nidhi (PM SVANidhi)

सहायक महाप्रबंधक, **राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने सूचित किया कि पीएम-स्वनिधि योजना के तहत राज्य में दिनांक 20.07.2024 तक **3,12,240** के लक्ष्य के सापेक्ष **2,32,597** आवेदन स्वीकृत किए हैं जिनमें से **1,99,289** आवेदनों में **रु. 237.89 करोड़** वितरित किए गए हैं। **33,308** स्वीकृत किए गए आवेदनों में ऋण वितरण लंबित है। सभी बैंकों से

जल्द से जल्द उक्त योजनान्तर्गत लंबित आवेदनों का निस्तारण करने एवं शत प्रतिशत लक्ष्य उपलब्ध करने का अनुरोध है।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

PM SVANidhi के अंतर्गत सबसे अधिक एवं सबसे कम प्रगति करने वाले बैंकों की सूची निम्नानुसार है-

Top Performing Banks as on 20.07.2024						Low Performing Banks as on 20.07.2024					
Sr. No.	Bank Name	Target alloted upto 31.12.2024	Disb (Account)	Disb (Amount) (Rs. in Cr)	%age ach.	Sr. No.	Bank Name	Target alloted upto 31.12.2024	Disb (Account)	Disb (Amount) (Rs. in Cr)	%age ach.
1	State Bank of India	54332	91590	11228.31	168.57	1	IndusInd Bank	6663	0	0.00	0.00
2	Bank of Baroda	28628	44010	5010.83	153.73	2	Bandhan Bank	12856	0	0.00	0.00
3	Bank of India	6933	8158	979.99	117.66	3	AU Small Finance Bank	11577	0	0.00	0.00
4	Bank of Maharashtra	2018	2204	253.50	109.24	4	Yes Bank	5721	6	0.60	0.10
5	Indian Overseas Bank	3702	3057	367.32	82.58	5	Axis Bank	10432	10	1.00	0.10

कम प्रगति वाले बैंकों से योजनान्तर्गत तिमाही के अंत तक प्रदर्शन सुधारने का अनुरोध है।

(कार्यवाही: इंडसइंड बैंक, यस बैंक, बंधन बैंक, एक्सिस बैंक एवं एयू स्माल फ़ाइनेंस बैंक)

अध्यक्ष, **राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने इंडसइंड बैंक, बंधन बैंक एवं एयू स्माल फ़ाइनेंस बैंक द्वारा PM SVANidhi के तहत शून्य प्रगति पर चिंता व्यक्त की। उन्होने निजी बैंकों के पास PM SVANidhi के लंबित आवेदनों की समीक्षा करने का अनुरोध किया।

प्रतिनिधि, **इंडसइंड बैंक** ने सूचित किया कि उक्त डाटा सही नहीं है एवं बैंक के केंद्रीय कार्यालय द्वारा यह डाटा प्रेषित किया गया है।

संयोजक, **राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने इंडसइंड बैंक, बंधन बैंक एवं एयू स्माल फ़ाइनेंस बैंक के प्रतिनिधियों द्वारा बिना उचित तैयारी के बैठक में सहभागिता करने पर असंतोष व्यक्त किया। उन्होने उक्त बैंकों को PM SVANidhi योजना के तहत अपनी प्रगति का root-cause analysis करने एवं प्रदर्शन सुधारने का निर्देश दिया।

(कार्यवाही: इंडसइंड बैंक, यस बैंक, बंधन बैंक, एक्सिस बैंक एवं एयू स्माल फ़ाइनेंस बैंक)

प्रतिनिधि, **स्वायत्त शासन विभाग**, **राजस्थान सरकार** ने सूचित किया कि-

- PM SVANidhi के आवेदन के बैंक खाते जिस बैंक में होते हैं, उसी बैंक को ऋण का आवेदन स्वतः ही route हो जाता है। अतः यदि निजी बैंकों द्वारा अच्छी मात्रा में PMJDY खाते खोले जाएँ, तो उनके PM SVANidhi के प्रदर्शन में सुधार होना अपेक्षित है।
- माननीय प्रधान मंत्री द्वारा हर महीने PM SVANidhi योजना के तहत राज्य के प्रदर्शन की समीक्षा की जा रही है। समीक्षा में पाया गया है कि बैंक PM SVANidhi के आवेदनों के निस्तारण में विलंब करते हैं जिसके कारण 14,000 आवेदन 2 महीने से अधिक समय एवं 27,000 आवेदन 3 महीने से अधिक समय से लंबित हैं। बैंकों से अनुरोध है कि इनका निस्तारण करें।
- सभी बैंक, विभाग द्वारा आयोजित अभियानों में स्वीकृत किए गए आवेदनों में अतिशीघ्र ऋण वितरण करें।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

संयुक्त शासन सचिव, **आयोजना विभाग**, **राजस्थान सरकार** की टिप्पणी- निजी बैंकों का प्रदर्शन सभी सरकारी योजनाओं के तहत असंतोषजनक है। सभी बैंक दूर-दराज के इलाकों में स्थित अपनी शाखाओं की सरकारी योजनाओं के तहत प्रगति की समीक्षा करें।

National Rural Livelihood Mission (NRLM)

सहायक महाप्रबंधक, **राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने सूचित किया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) के तहत लक्ष्य **1,36,700** के सापेक्ष दिनांक 30.06.2024 तक **15,594 खातों (11.41%)** में **रु 16,529 करोड़ (6.48%)** का ऋण वितरण किया गया है।

NRLM के तहत राज्य के उच्चतम एवं न्यूनतम उपलब्धि वाले बैंक निम्नानुसार हैं-

Top Performing Major Banks as on 30.06.2024					Low Performing Major Banks as on 30.06.2024				
S. No.	Particulars	Target A/c	Disbursed A/c	% Disb against Target	S. No.	Particulars	Target A/c	Disbursed A/c	% Disb against Target
1	CANARA BANK	1050	371	35.33	1	BOM	90	4	4.44
2	INDIAN BANK	2200	667	30.32	2	RSCB	3300	28	0.85
3	CENTRAL BANK OF INDIA	1530	404	26.41	3	IDBI BANK LTD	100	0	0.00
4	BANK OF BARODA	25000	4994	19.98	4	HDFC BANK LTD	12470	0	0.00
5	RMGB	5690	978	17.19	5	ICICI BANK LTD	19000	0	0.00

कम प्रगति करने वाले सभी बैंकों से योजनान्तर्गत अच्छा प्रदर्शन करने हेतु अनुरोध किया।

(कार्यवाही: राजस्थान राज्य सहकारी बैंक, आईडीबीआई बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एचडीएफ़सी बैंक एवं आईसीआईसीआई बैंक)

प्रतिनिधि, राजीविका, राजस्थान सरकार ने सूचित किया कि-

- 25.08.2024 को माननीय प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में SHG महिलाओं के credit linkage हेतु आयोजित कार्यक्रम में आवश्यक सहयोग प्रदान करने के लिए सभी बैंकों का धन्यवाद। इस कार्यक्रम हेतु राज्य की उपलब्धि (रु 152 करोड़), आवंटित लक्ष्यों (रु. 127 करोड़) से अधिक रही।
- SHG credit linkage में एचडीएफ़सी, इंडियन बैंक, यूको बैंक, केनरा बैंक एवं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का प्रदर्शन संतोषजनक है जबकि बीआरकेजीबी, आईसीआईसीआई, भारतीय स्टेट बैंक, राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक, पंजाब नेशनल बॅंक, बैंक ऑफ बड़ौदा एवं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का प्रदर्शन असंतोषजनक है/ अद्यतित नहीं किए जाने के कारण पोर्टल पर परिलक्षित नहीं हो रहे हैं।
- सभी बैंक पहली डोज़ में न्यूनतम रु 1.5 लाख एवं दूसरी डोज़ में न्यूनतम रु 3.0 लाख वितरित करना सुनिश्चित करें।
- Individual Finance के आवेदनों के समय से निस्तारण पर विशेष ध्यान दे।
- बैंक SHG credit linkage एवं लखपति दीदी के लंबित ऋण आवेदनों (लगभग 12,525) का समय से निस्तारण करें।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

<u>Performance under Govt. Sponsored Programmes during FY 2024-25</u>

सहायक महाप्रबंधक, **राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत राज्य में प्रगति से सदन को निम्नानुसार अवगत कराया-

Sr.	Name of Scheme	Targets (No.)	No. of Appl. Spon.	No. of Appl. Sanc.	No. of Appl. Disb.	No. of Appl. Pending	% Ach
1	Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP) (as on 30.06.2024)	-	1263 No. 80.87 Cr (MM)	641 No. 55.62 Cr (MM)	311 No. 28.78 Cr (MM)	1172 No. 96.16 Cr (MM)	-
2	Agriculture Infrastructure Fund (AIF) (as on 31.07.2024)	3250 Cr	312.14 Cr	189.65 Cr	53.27 Cr	73.62 Cr	5.36
3	PM Formalization of Micro food processing Enterprises (PMFME) (as on 31.07.2024)	7331	307	74	39	184	1.01
4	National Urban Livelihood Mission (NULM) – Individuals & Group (as on 30.06.2024)	2630	2781	570	555	2211	21.67

5	National Urban Livelihood Mission (NULM) – SHG (as on 30.06.2024)	1065	984	223	222	761	20.94
6	Mukhya Mantri Laghu Udyog Protsahan Yojana (MLUPY) (as on 30.06.2024)	5200	8831	1254	1115	6940	24.12
7	Dr. Bhimrao Ambedkar Rajasthan Dalit Aadivasi Udyam Protsahan Yojana – 2022 (BRUPY) (as on 30.06.2024)	2000	239	87	66	233	4.35
8	Mukhya Mantri Yuwa Udyam Protsahan Yojana (MYUPY) (as on 30.06.2024)	200	746	74	73	565	37.00
9	Indira Mahila Shakti Udyam Protsahan Yojna (IMSUPY) (as on 30.06.2024)	1200	5016	123	71	4893	10.25

प्रतिनिधि, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार की टिप्पणी-

- IMSUPY के तहत लगभग 5,000 आवेदन लंबित हैं।
- योजनान्तर्गत 13,700 आवेदन बिना उचित कारण के अस्वीकृत कर दिये गए हैं। इनमे से एक्सिस बैंक द्वारा 82%, आईसीआईसीआई द्वारा 79% एवं इंडियन ओवरसीज़ बैंक द्वारा 74% प्राप्त आवेदनों को अस्वीकार कर दिया गया है। बैंकों से अनुरोध है कि ऋण आवेदन को अस्वीकार करने के स्थान पर स्पष्ट कारणों के साथ वापस भेज दिया करें जिससे उसकी कमियों में सुधार करके बैंकों को पुनः प्रेषित किया जा सके।
- बैंकों से अनुरोध है कि IMSUPY योजना के संभावित लाभार्थियों का विभाग के ज़िला कार्यालय से संपर्क करावे।
- सभी बैंक शाखाओं में कार्यरत स्टाफ को यह सूचित करें कि IMSUPY योजना को सरकार द्वारा बंद नहीं किया गया है, अतः इस योजना के तहत अधिक से अधिक संभावित लाभार्थियों को ऋण प्रदान करना जारी रखें।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

प्रतिनिधि, उद्योग विभाग, राजस्थान सरकार ने सदन को बताया कि-

- MLUPY एवं MYUPY योजना योजनाएँ 31.07.2024 को बंद हो गयी हैं। सभी बैंक दोनों योजनाओं में 31 अगस्त 2024 तक स्वीकृति एवं 30 सितंबर 2024 तक ऋण वितरण की कार्यवाही सुनिश्चित करें जिसके पश्चात लंबित आवेदन स्वतः ही अस्वीकृत हो जाएंगे।
- BRUPY के तहत जुलाई 2024 तक की प्रगति 6.5% है एवं लगभग 3,300 आवेदन निस्तारण हेतु लंबित हैं। बैंकों से बिना विलंब योजनान्तर्गत आवेदनों का निस्तारण करने का अनुरोध है।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

संयुक्त शासन सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार की टिप्पणी- 28 जिलों में BRUPY के तहत शून्य ऋण स्वीकृत किए गए हैं जो स्वीकार्य नहीं है। SC-ST-POP के तहत राज्य में नगण्य प्रदर्शन है।

प्रतिनिधि, एससी एसटी वित्त एवं विकास सहकारी निगम लि. ने सूचित किया कि SC-ST-POP के 1400 आवेदन बैंकों के पास लंबित है एवं मात्र 50 व्यक्तियों को योजनान्तर्गत ऋण दिया गया है। बैंकों से अनुरोध है कि SC-ST-POP एवं PMMY के लाभार्थियों की सूची विभाग को प्रेषित करें जिससे लाभार्थियों को अनुदान राशि प्रदान की जा सके।

Prime Minister Employment Generation Programme (PMEGP)

सहायक महाप्रबंधक, **राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने सूचित किया कि-

- राज्य में पीएमईजीपी के तहत राशि **रू. 58.02 करोड़ (मार्जिन राशि)** के लक्ष्य के सापेक्ष दिनांक 22.07.2024 तक बैंकों द्वारा 311 आवेदनों में राशि **रू. 28.78 करोड़** मार्जिन मनी के ऋण वितरित किए गए है। **रु 96.16 करोड़** के मार्जिन मनी क्लेम विभाग के स्तर पर लंबित हैं।
- वित्तीय वर्ष 2024-25 मे पीएमईजीपी के लक्ष्य काफी कम होने के कारण संबन्धित विभाग से इस पर पुनर्विचार हेतु अनुरोध है।

सहायक महाप्रबंधक, **राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने सूचित किया कि दिनांक 30.06.2024 तक की प्रगति निम्नानुसार है-

Bank-wise PMEGP progress as on 30.06.2024							(₹. In Cr.)	
Sr. No.	Forwarded to Bank		Sanctioned by Bank		Margin Money Claimed		MM Disbursed	
	No of Prj.	MM Involve	No of Prj.	MM Involve	No of Prj.	MM Involve	No of Prj.	MM Involve
A	1263	80.87	641	55.62	1176	96.56	311	28.78

PMEGP के अंतर्गत अधिकतम एवं न्यूनतम प्रगति करने वाले बैंकों की सूची निम्नानुसार है-

Top Performing Banks under as on 30.06.2024				Lowest Performing Banks under as on 30.06.2024			
Sr. No.	Banks	MM Claim (₹. In Cr)		Sr. No.	Banks	MM Claim (₹. In Cr)	
		No of Prj.	MM Involve			No of Prj.	MM Involve
1	BANK OF BARODA	82	930.46	1	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	1	17.50
2	PUNJAB NATIONAL BANK	49	363.05	2	HDFC BANK	1	11.84
3	CANARA BANK	22	231.50	3	PUNJAB AND SIND BANK	1	9.79
4	CENTRAL BANK OF INDIA	17	195.32	4	AXIS BANK LTD	0	0.00
5	UCO BANK	33	189.20	5	AU SMALL FIN BANK LTD	0	0.00
							Source: PMEGP Portal

योजनांतर्गत असराहनीय प्रदर्शन वाले बैंकों से इस वित्तीय वर्ष बेहतर प्रदर्शन करने का अनुरोध है।

(कार्यवाही: एयू स्माल फ़ाइनेंस बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफ़सी बैंक, कोटक महिंद्रा, पंजाब एंड सिंध बैंक)

सभी बैंकों से अनुरोध है कि उक्त योजना के तहत अधिक से अधिक आवेदनों हेतु ऋण प्रदान करें।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

PMFME Scheme

दिनांक 31.07.2024 तक PMFME के तहत एजेंसी-वार प्रगति निम्न प्रकार है:

Bank Wise Progress under PM FME for FY 2024-25 as on 31.07.2024 (₹. in Cr.)													
S. N.	Bank	Individual Unit Target	Application Received		Application Sanctioned		Application Disbursed		Application Rejected		Pending Applications		%age Achievement
		A/c	A/c	Amt.	A/c	Amt.	A/c	Amt.	A/c	Amt.	A/c	Amt.	
A	Public Sector Bank	**4439**	207	52.38	39	11.82	18	2.73	42	8.92	126	31.64	0.88
B	Private Sector Bank	**1421**	56	24.05	18	10.05	4	0.76	2	0.25	36	13.75	1.27
C	Regional Rural Bank	**1037**	19	4.05	1	0.15	1	0.10	2	0.24	16	3.66	0.10
D	Co-Operative Bank	**244**	17	0.51	16	0.50	16	0.08	0	0.00	1	0.01	6.56
E	Small Finance Bank	**190**	8	3.55	0	0.00	0	0.00	3	1.54	5	2.01	0.00
	Grand Total	**7331**	**307**	**84.53**	**74**	**22.52**	**39**	**3.68**	**49**	**10.95**	**184**	**51.06**	**1.01**

बैंकों से PMFME के तहत शत-प्रतिशत लक्ष्य उपलब्ध करने का अनुरोध है।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

Agriculture Infrastructure Fund (AIF)

कृषि अवसंरचना निधि के तहत दिनांक 31.07.2024 तक बैंकों की प्रगति निम्नानुसार है:-

Progress under Agriculture Infrastructure Fund as on 31.07.2024 (₹. in Cr.)

Sr. No.	Bank	Application forwarded to Banks		Application Sanctioned by Banks		Out of Sanctioned, pending for Disb.		Out of Sanctioned, App. Disb. By Bank		Application Pending with Bank		% age Ach (sanction)
		No.	Amt.	No.	Amt.	No.	Amt.	No.	Amt.	No.	Amt.	
A	Public Sector Bank	268	244.65	185	163.25	85	122.45	100	40.80	30	34.51	7.95
B	Private Sector Bank	103	49.05	21	19.81	15	8.00	6	11.81	60	27.26	2.89
C	Regional Rural Bank	7	10.54	4	6.28	3	5.62	1	0.66	3	4.26	1.15
D	Co-Operative Bank	7	1.95	0	0.00	0	0.00	0	0.00	7	1.95	0.00
E	Small Finance Bank	3	5.64	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	5.64	0.00
	Rajasthan Total	**389**	**312.14**	**211**	**189.65**	**104**	**136.38**	**107**	**53.27**	**103**	**73.62**	**5.36**

बैंकों से कृषि अवसंरचना निधि (AIF) के तहत स्वीकृत किए हुये ऋण आवेदन पत्रों में ऋण वितरण करवाने का अनुरोध है।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

Pradhan Mantri Mudra Yojna:

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में 27.07.2024 तक **3,10,844** खातों में **रु 4,655.36 करोड़** का ऋण वितरण रिपोर्ट किया गया। सभी बैंकों से अनुरोध है बिना विलंब पोर्टल पर PMMY के लक्ष्य अद्यतित करें।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

उक्त योजनान्तर्गत श्रेणीवार प्रगति निम्नानुसार है :

Sr. No.	Category	No. of A/c's	Disbursed Amt. cr
1	Shishu	1,41,435 (45.50%)	530
2	Kishore	1,46,599 (47.16%)	2329
3	Tarun	22,810 (7.34%)	1796
	Total	**3,10,844**	**4,655**

- सभी बैंक **PMMY** के तहत लक्ष्यों को संबन्धित पोर्टल पर upload करें एवं योजनान्तर्गत शत प्रतिशत लक्ष्य उपलब्ध करने का अनुरोध है।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

Stand Up India Scheme (SUI)

स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत योजना की शुरुआत से दिनांक 01.08.2024 तक राज्य में **12,618** आवेदनों में राशि **रु. 2,808.41 करोड़** के ऋण स्वीकृत किए गए एवं **6,751** खातों में **रु 1,284.02 करोड़** का ऋण वितरण किया गया। वित्तीय वर्ष 2024-25 में दिनांक 01.08.2024 तक **रु. 249.18 करोड़** के **1,127** आवेदन स्वीकृत किए गए एवं **176** खातों में **रु 43.25 करोड़** का ऋण वितरण किया गया।

समस्त अग्रणी जिला प्रबंधकों से प्रत्येक डीएलआरसी/डीसीसी बैठक में नियमित रूप से योजना की प्रगति की समीक्षा करने का अनुरोध है।

(कार्यवाही: समस्त अग्रणी ज़िला प्रबन्धक)

बैंकों से स्वीकृत किए गए ऋणों में जल्द-से-जल्द ऋण वितरण करने का अनुरोध है।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

Sector wise NPA Position as on 30th June, 2024

राज्य में क्षेत्र वार NPA निम्नानुसार है-

कुल- 3.51%

कृषि- 7.84%

एमएसएमई- 2.63%

अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र- 1.87%

कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र- 4.79%

कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के NPA का क्षेत्र वार वर्गिकरण निम्नानुसार है-

कुल कृषि- 70.57%

कुल एमएसएमई- 24.84%

कुल अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र- 4.59%

Comparison chart of NPA (%)

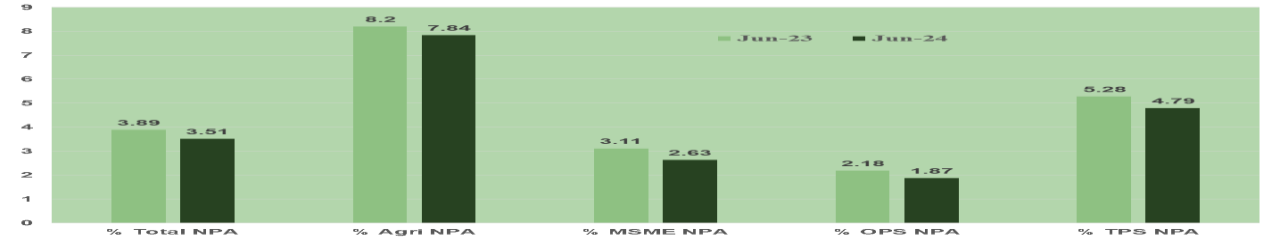

Education Loan

बैंकों द्वारा वर्ष 2024-25 में जून, 2024 तिमाही तक राज्य में **5,654** छात्रों को राशि **रू 175.98 करोड़** के शिक्षा ऋण वितरित किए गए हैं एवं दिनांक 30.06.2024 तक **43,389** खातों में **रु 2,947.06** करोड़ की राशि outstanding है।

बैंकों से प्राप्त सूचना के अनुसार विद्यालक्ष्मी पोर्टल के माध्यम से दिनांक 30.06.2024 तक **5,654** खातों में **रु 175.98 करोड़** का ऋण वितरण किया गया है।

उप-महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बैठक में उपस्थित मंचासीन सदस्यों सहित केंद्र एवं राज्य सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, बैंक तथा अन्य सभी विभागों के अधिकारियों का धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ बैठक का समापन किया।

***